

क्या डूबने वाला है आईसीआईसीआई बैंक

मजदूर मोर्चा ब्यूरो/ गिरीश मालवीय

भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई क्या डूबने की कगार पर है... यह सवाल अचानक पूछा जाने लगा है। इस बैंक की सीईओ चंदा कोचर के नाम लुकआउट नोटिस भारत सरकार ने जारी कर दिया है। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और देवर राजीव कोचर पर भारत की सभी जांच एजेंसियां नजर रख रही हैं। चंदा कोचर के साथ साथ विडियोकॉन कंपनी के मालिक वेणु गोपाल धूत के खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी हुआ है।

अमेरिका में 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो उस वक्त वहां का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक - लहमन बैंक - डूब गया था। उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। आईसीआईसीआई बैंक अगर लहमन बैंक के अंदाज में डूबता है तो सोचिए भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा... भारत में सरकारी बैंक एसबीआई के टक्कर में यह बैंक खड़ा हुआ था। अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी खानदान तक के लोग इस बैंक के डायरेक्टरशिप में रहे या हैं। यानी देश की सबसे सशक्त और रसूखदार लॉबी का हाथ आईसीआईसीआई बैंक के सिर पर है। इसके बावजूद यह बैंक अब डूबने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। वजह यही है कि इसने भी इतने बड़े पैमाने पर कर्ज बांटे हैं कि इसकी कमर टूट गई है। प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा एनपीए इसी बैंक का है।

पूंजी की लूट में चोर-चोर मौसेरे भाई
भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के तहत खड़े किए गए प्राइवेट बैंकों को दरअसल सरकारी और गैर सरकारी पूंजी की लूट के लिए ही खड़ा किया गया था। अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक लाकर भारत की आम जनता को घुट्टी में आईसीआईसीआई बैंक के विज्ञापनों के जरिए घुट्टी में पिलाया गया कि यही बैंक है जो आपका ख्याल रखता है।...जिसकी तकनीक

का सहारा लेकर आप कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हैं। हमारे देखते देखते ही इस बैंक की शाखाएं देशभर में खुल गईं। सरकारी बैंक जहां नहीं पहुंच सके थे, वहां भी इस बैंक की शाखाएं पहुंच गईं। सरकारी बैंकों को ऐसा बना दिया गया या उनकी ऐसी कार्य संस्कृति विकसित होने दी गई कि वहां के बाबू भ्रष्ट होते हैं, कामचोर होते हैं। बैंक यूनियनों ने भी इस कार्य संस्कृति को विकसित होने देने में अपनी भूमिका अदा होने दी। नतीजा यह निकला कि परेशान बैंक ग्राहक प्राइवेट बैंकों की शरण में जाने लगा। चूंकि आईसीआईसीआई पहला प्राइवेट बैंक था तो उसे बाजार में पहले आने का सबसे ज्यादा लाभ मिला। लेकिन ग्राहक नहीं जानता था कि प्राइवेट बैंक उसे लूटने आ रहे हैं और जल्द ही उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे।

तकनीक के दम पर जब प्राइवेट बैंकों ने सरकारी बैंकों को पछड़ दिया और हमें बैंकिंग के मामले में आरामतलब कर दिया तब ये बैंक अपना असली चेहरा लेकर सामने आ गए। हमें रोजाना शर्तें बताई जाने लगीं कि कम से कम दस हजार रुपये आपको बैंक में रखने होंगे। चेक काटोगे तो पैसे भरने होंगे। मामूली गलती पर भी चेक लौटा तो पैसे भरने होंगे। हम एसएमएस भेजेंगे तो हर बार पैसे काटेंगे। आपको पासबुक नहीं मिलेगी...और न जाने क्या-क्या शर्तें बताई जाने लगीं। बैंक के डूबने पर हमारा सिर्फ एक लाख रुपया ही सुरक्षित है, बैंक के डूबने पर आपका बाकी पैसा भी डूब जाएगा। देखिए...कितना घृणित खेल था। हमारा पैसा लेकर पूंजीपतियों को और लोन दिए जा रहे थे। वो लोग पैसे से पैसा कमा रहे थे, प्राइवेट बैंक उनकी मदद कर रहे थे।

कफनचोर सलाहकार
देश में मोदी सरकार के आने के बाद सरकार को लगातार सलाह दी जा रही है कि एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी सरकारी

बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद पानगढ़िया ने हाल ही में पूंजीपतियों के सबसे बड़े अखबार टाइम्स आफ इंडिया में एक लेख लिखकर सलाह दी है कि सरकारी बैंकों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाए। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि सरकारी बैंकों का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पीएनबी और एसबीआई को लूटकर फरार हो गए। यह सरकारी बैंकों के प्रबंधन की नाकामी थी जिसकी वजह से यह लोग बैंकों को लूटकर भागे। दरअसल, देश के पूंजीपतियों ने जो मजे प्राइवेट बैंकों की आड़ में लिए हैं, वे उस मजे का स्वाद और बढ़ाने के लिए बाकी बैंकों को भी चट कर जाना चाहते हैं। अरविंद पानगढ़िया का लेख छापने वाले टाइम्स आफ इंडिया से कोई पूछे कि सरकार ने प्राइवेट बैंकों का लाइसेंस जारी करने के समय टाइम्स बैंक के नाम से भी तो लाइसेंस दिया था। देश के कई शहरों में टाइम्स बैंक खुले लेकिन टाइम्स ग्रुप इन्हें चला नहीं पाया। आखिरकार इसे येस बैंक ने खरीद लिया और अब टाइम्स बैंक येस बैंक के रूप में सामने आ गया।

आईसीआईसीआई का गोरखधंधा
आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बड़ा घोटाला पकड़ा गया है पर कोई भी खुल कर के कुछ कहने को तैयार नहीं है। क्योंकि अरविंद पानगढ़िया ओर उर्जित पटेल जैसे अर्थशास्त्रियों की बैंकिंग के बारे में कसमझ की पोल खुलने का पूरा अंदेश है, दोनों ही खुलकर सरकारी बैंकों के निजीकरण के पक्ष में आ गए थे।

गुरुवार रात आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई अब उससे पूछताछ कर रही है।

अब यह खेल समझिए जो चंदा कोचर ने, उनके पति दीपक कोचर ने, विडियोकॉन

के मालिक वेणुगोपाल धूत ने और चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर ने मिलकर के खेला है।

आपको यहां इस खेल की कोई जानकारी नहीं होगी न ही इसे अभी तक गलत प्रैक्टिस बताता हुआ रिजर्व बैंक का बयान आया है लेकिन अमेरिका में आईसीआईसीआई बैंक की इस हरकत पर ICICI बैंक को क्लास एक्शन कानूनी मामले और एक महंगे सेटलमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में आईसीआईसीआई बैंक से सम्बंधित संस्थान के शेयर तेजी से नीचे गिर गए हैं

दरअसल, चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक को अपने फैमिली बिजनेस की तरह चला रही थीं और यह बात पिछले दिनों ही सामने आ चुकी है कि किस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री यानी विडियोकॉन से चंदा कोचर अपने पति दीपक कोचर की पार्टनरशिप में रिन्यूएबल एनर्जी की एक कम्पनी खुलवाती है फिर एक बहुत बड़ा लोन मंजूर करने की एवज में उस कम्पनी का पूरा अधिपत्य, दीपक कोचर को विडियोकॉन वाले धूत साहब ट्रांसफर कर देते हैं साथ ही उस कम्पनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं।

लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दो दिनों में इस कहानी में बहुत बड़ा चेंज आया है और वो चेंज ये है कि एक नए किरदार की एंट्री हुई है और वो है चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर जो एक खास तरीके का बिजनेस चलाते हैं।

क्या है चंदा कोचर के देवर का धंधा
राजीव अविस्ता एडवाइजरी ग्रुप नाम की कंपनी चलाते हैं। यह कंपनी बड़ी कंपनियों की बैंकों के साथ लोन रिस्ट्रक्चरिंग में मदद करती है यानी जिन इंडस्ट्री का कर्जा लगभग डूब गया होता है उस इंडस्ट्री और बैंक के बीच एक प्रकार की मध्यस्थता का रास्ता सुझा देते हैं, ओर साथ ही उन कंपनियों को नया लोन भी दिलवा देते हैं इस काम को कॉरपोरेट की भाषा में क्लाइट्स के कर्ज को रीस्ट्रक्चरिंग

के लिए एडवाइस किया जाना बोला जाता है।

एविस्ता एडवाइजरी वो ही कंपनी है, जिसने पिछले 6 साल में सात बड़ी कंपनियों के 1.7 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा और लोन दिलाने में मदद की, और कमाल की बात तो यह है कि इन सभी कंपनियों ने आईसीआईसीआई बैंक से एक ही समय पर कर्ज लिया था। कुछ कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं जयप्रकाश एसोसिएट, जीटीएल इंफ्रा, सुजलॉन औकिकर जयप्रकाश पावर आदि। विडियोकॉन भी अविस्ता एडवाइजरी का एक बड़ा क्लाइंट है।

जब आईसीआईसीआई बैंक से पूछा गया कि किस बिना पर आपने एविस्ता के राजीव कोचर और चंदा कोचर के नजदीकी रिश्तेदार होने पर प्रश्न नहीं उठाया तो आईसीआईसीआई का कहना था कि कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के तहत पति का भाई रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए बैंक इसे गलत नहीं मानता है।

अब बताइए ये घटिया जवाब किस तरह से गले उतर सकता है। राजीव कोचर भी कह देते हैं कि इसमें हितों के टकराव का कोई मामला नहीं है। सलाहकार चुनने की पूरी प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी होती है। लेकिन बिजनेस करने वाला हर आदमी जानता है कि जब इस कम्पनी वाले का इतना करीबी रिश्तेदार बैंक के CEO के पद पर बैठा हो तो किसी और कम्पनी से लोन का रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करवाया जाए।

लिहाजा यह फायदा धूत साहब ने पूरी तरह से उठाया और एविस्ता की सेवाएं लेकर आईसीआईसीआई बैंक में अपने लोन 3,250 करोड़ रुपये को 2017 में राइट ऑफ करवा लिया, और ऐसे ही बाकी कम्पनियों ने भी किया होगा जिसके कच्चे चिट्ठे खुलना अभी बाकी है। अब अगर मोदी भक्तों को इसमें भी किसी को कोई घोटाला नहीं दिख रहा तो वह अपने दिमाग का इलाज करवा ले।

चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में लिया

आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अब उससे पूछताछ कर रही है।

अब यह खेल समझिये जो चंदा कोचर ने, उनके पति दीपक कोचर ने, विडियोकॉन के वेणु गोपाल धूत ने और चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर ने मिलकर के खेला है,.....

आपको यहाँ इस खेल की कोई जानकारी नहीं होगी न ही इसे अभी तक गलत प्रैक्टिस बताता हुआ रिजर्व बैंक का बयान आया है लेकिन अमेरिका में आईसीआईसीआई बैंक की इस हरकत पर ICICI बैंक को 'क्लास एक्शन' कानूनी मामले और एक महंगे सेटलमेंट का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिका में आईसीआईसीआई बैंक से सम्बंधित संस्थान के शेयर तेजी से नीचे गिर गए हैं।

दरअसल चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक को अपने फैमिली बिजनेस की तरह चला रही थी और यह बात पिछले दिनों ही सामने आ चुकी है कि किस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री यानी विडियोकॉन से चंदा कोचर अपने पति दीपक कोचर की पार्टनर शिप में रिन्यूएबल एनर्जी की एक कम्पनी खुलवाती है फिर एक बहुत बड़ा लोन मंजूर करने की एवज में उस कम्पनी का पूरा अधिपत्य, दीपक कोचर को विडियोकॉन वाले धूत साहब ट्रांसफर कर देते हैं साथ ही उस कम्पनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं।

लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दो दिनों में इस कहानी में बहुत बड़ा चेंज आया है और वो चेंज ये है कि एक नए किरदार की एंट्री हुई है और वो है चंदा

दरअसल चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक को अपने फैमिली बिजनेस की तरह चला रही थी और यह बात पिछले दिनों ही सामने आ चुकी है कि किस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री यानी विडियोकॉन से चंदा कोचर अपने पति दीपक कोचर की पार्टनर शिप में रिन्यूएबल एनर्जी की एक कम्पनी खुलवाती है फिर एक बहुत बड़ा लोन मंजूर करने की एवज में उस कम्पनी का पूरा अधिपत्य, दीपक कोचर को विडियोकॉन वाले धूत साहब ट्रांसफर कर देते हैं साथ ही उस कम्पनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं।

कोचर के देवर राजीव कोचर जो एक खास तरीके का बिजनेस चलाते हैं।

राजीव अविस्ता एडवाइजरी ग्रुप नाम की कंपनी चलाते हैं यह कंपनी बड़ी कंपनियों की बैंकों के साथ लोन रिस्ट्रक्चरिंग में मदद करती है यानी जिन इंडस्ट्री का कर्जा लगभग डूब गया होता है उस इंडस्ट्री ओर बैंक के बीच एक प्रकार की मध्यस्थता का रास्ता सुझा देते हैं, ओर साथ ही उन कंपनियों को नया लोन भी दिलवा देते हैं इस काम को कारपोरेट की भाषा में

क्लाइट्स के कर्ज को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एडवाइस किया जाना बोला जाता है।

एविस्ता एडवाइजरी वो ही कंपनी है, जिसने पिछले 6 साल में सात बड़ी कंपनियों के 1.7 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा और लोन दिलाने में मदद की।

ओर कमाल की बात तो यह है कि इन सभी कंपनियों ने ICICI बैंक से एक ही समय पर कर्ज लिया था। कुछ कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं जयप्रकाश एसोसिएट, जीटीएल इंफ्रा, सुजलॉन और जयप्रकाश पावर आदि विडियोकॉन भी अविस्ता एडवाइजरी का एक बड़ा क्लाइंट है।

जब आईसीआईसीआई बैंक से पूछा गया कि किस बिना पर आपने एविस्ता के राजीव कोचर ओर चंदा कोचर के नजदीकी रिश्तेदार होने पर प्रश्न नहीं उठाया तो ICICI का कहना था कि कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के तहत पति का भाई रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए बैंक इसे गलत नहीं मानता है।

अब बताइये ये घटिया जवाब किस तरह से गले उतर सकता है राजीव कोचर भी कह देते हैं कि %इसमें हितों के टकराव का कोई मामला नहीं है। सलाहकार चुनने की पूरी प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी होती है।

लेकिन बिजनेस करने वाला हर आदमी जानता है कि जब इस कम्पनी वाले का इतना करीबी रिश्तेदार बैंक के CEO के पद पर बैठा हो तो किसी ओर कम्पनी से लोन का रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करवाया जाए।

लिहाजा यह फायदा धूत साहब ने पूरी तरह से उठाया और एविस्ता की सेवाएं लेकर आईसीआईसीआई बैंक में अपने लोन 3,250 करोड़ रुपये को 2017 में राइट ऑफ करवा लिया, ओर ऐसे ही बाकी कम्पनियों ने भी किया होगा जिसके कच्चे चिट्ठे खुलना अभी बाकी है। अब यदि इसमें भी किसी को कोई घोटाला नहीं दिख रहा तो वह अपने दिमाग का इलाज करवा लें।

निजी क्षेत्र के बैंकों की बेशर्मी देखिए

निजी क्षेत्र की बैंकों की आप बेशर्मी देखिए कि चंदा कोचर जिस समारोह में राष्ट्रपति जा रहे हैं उसमें मुख्य अतिथि बनने से इन्कार तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा घोटाला सामने के आने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में अपना पद नहीं छोड़ रही

सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक की बात नहीं है एक्सिस बैंक का बोर्ड मित्रते कर रहा है कि शिखा शर्मा को चौथा टर्म यानी तीन साल का एक्सटेंशन ओर दे दिया जाए ओर इस बात की घोषणा बैंक का बोर्ड शिखा शर्मा के कार्यकाल की समाप्ति के 11 महीने पहले ही कर देता है कि मैडम 2021 तक बैंक की प्रमुख बनी रहेंगी

एक्सिस बैंक की खराब परफॉरमेंस और लगातार बिगड़ती एसेट क्वालिटी के बावजूद बैंक का बोर्ड शिखा शर्मा को तीन साल के लिए बैंक प्रमुख बनाने पर क्यों तुला है समझ के बाहर है

एक्सिस बैंक की हालत इस कदर खराब है कि आरबीआई ने एक्सिस बैंक को उन बैंकों की सूची से हटा दिया है जिन्हें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सोने व चांदी के आयात की अनुमति है जबकि निजी क्षेत्र का एक्सिस बैंक पिछले साल सर्राफा के सबसे बड़े आयातक बैंकों में से एक रहा था रिजर्व बैंक ने उन 16 बैंकों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की जिन्हें मौजूदा वित्त वर्ष में सोने-चांदी के आयात की अनुमति रहेगी। इसमें एक्सिस बैंक का नाम नहीं है। पिछले साल जिन 19 बैंकों को यह अनुमति थी उनमें प्रमुख आयातकों में से एक एक्सिस बैंक रहा था। इस अनुमति के तहत बैंक कच्चे सोने व चांदी का आयात कर उसे बेचते हैं

आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को पिछले महीने सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया था ये दोनों ही टॉप बैंक अधिकारी उस कंसोर्टियम की सदस्य थीं, जिन्होंने नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी की कंपनी गीताजलि ग्रुप के लिए 3280 करोड़ रुपये के बैंक लोन की मंजूरी दी थी।

जब पीएनबी घोटाला सामने आया था तो उसमें यह पता चला कि बैंको ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का आदेश नहीं माना कि कोई भी अधिकारी एक शाखा में तीन साल से ज्यादा नहीं टिक सकता, लेकिन जब बड़े बड़े अधिकारियों और सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों की बात आती है तो सारे नियम कायदे धरे रह जाते हैं, चंदा कोचर के मामले से साफ हो जाता है कि एक व्यक्ति को लगातार यदि कई सालों से बैंक प्रमुख के पद पर रखा जाता है तो वह किस तरह से अपने निजी हितों को प्राथमिकता देते हुए पब्लिक के जमा पैसे में हेराफेरी करने से नहीं चूकता.....

लेकिन इस पूरे प्रकरण में रिजर्व बैंक क्यों धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहा है यह भी समझ के परे है....